nations and help to build a world based on equality and cooperation among nations.

I am sure the House will join me in the hope that bloodshed and strife in Angola will soon come to an end so that the Government and people of Angola can address themselves unhindered to the task of national reconstruction at home, fighting racism and minority regimes in Africa and contributing to resolve the many international problems confronting the community of nations.

**THE HOUSE OF THE PEOPLE (EXTENSION OF DURATION) BILL, 1976** —*CONTD*:

MR CHAIRMAN : Shri Yogendra Sharma may speak.

**श्री योगेन्द्र शर्मा** (बिहार): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी अवधि बढ़ा ली है। उसमें राज्य सभा को क्या करना है ? राज्य सभा की अवधि न ही बढ़ती है न ही घटती है, और यदि लोक सभा ने अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करके अपनी अवधि बढ़ा ली है, तो हमें उसके पीछे-पीछे चलना है, उसका समर्थन करना है, इसके सिवाय और क्या कहना है। हम तो नहीं कह सकते कि तुम अपनी अवधि नहीं बढ़ाओ। हमारी अवधि बढ़ाने की बात होती तब हम विचार कर सकते थे।

**श्री ओउम् प्रकाश त्यागी** (उत्तर प्रदेश) : राज्य सभा को यही समझे हैं, पीछे-पीछे चलना ?

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : लोक सभा के अधिकार के मामले में पीछे नहीं कह सकते हैं। लोक सभा का जो अधिकार है उसके अधिकार की तो हम रक्षा करेंगे । जब यह अवधि बढ़ायी जा रही है, तो हम सरकार से यही आशा करेंगे कि जो समय इस प्रकार मिलता है उस समय का सदुपयोग 20-सूत्री कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक और शीघ्रता के साथ पालन करने में उपयोग किया जाए ।

श्रीमन्, यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि जब 1971 में लोक सभा के चुनाव हुए थे, तो किस परिस्थिति में वह चुनाव हुए थे ? किन सवालों को लेकर चुनाव हुए थे ? चुनाव उन सवालों को लेकर हुए थे कि देश की स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी, या देश की स्थिति को गतिशील दिशा में बदला जाएगा ? यथास्थिति और प्रगति, इन दो शक्तियों के बीच में 1971 के समय लोक सभा का संघर्ष हुआ था, और भारतीय जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने मत प्रगति के पक्ष में दिया और कांग्रेस पार्टी विजयी हुई। बावजूद इसके कि प्रतिक्रियावादी "ग्रैण्ड एलायंस" की ताकतों ने चुनौती दी थी—प्रगति की शक्ति को यथास्थिति की शक्ति के सामने खड़ा कर दिया—जनतांत्रिक पद्धति का तकाजा था कि ग्रैण्ड एलायंस की ताकतों को जनता के उस फैसले के सामने सिर झुकाना था, लेकिन उन्होंने सिर झुकाने के बदले फासिस्टी तरीके अख्तियार किए ताकि जनता के वह मैन्डेट पूरे न किए जाएं। पिछले 2 वर्षों में हमने जो कुछ भी देखा है, यही देखा है कि जनता के मैन्डेट को ठुकराने के फासिस्ट तरीके अपनाए गए। ऐसी स्थिति में देश के सामने संकट आया; देश का बहुमूल्य समय और साधन इन फासिस्ट ताकतों का सामना करने और उन्हें कुचलने में लगा। इसलिए हम समझ सकते हैं कि 1971 के मैंडेट की बहुत सी बातें पूरी नहीं हो सकीं। और इस बात का औचित्य है कि जो अवधि बढ़ायी जा रही है उस अवधि में उनके द्वारा 1971 के मैन्डेट को पूरा करने की अधिक से अधिक कोशिश हो। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ हम लोक सभा के फैसले का समर्थन करते हैं।

**श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** (राजस्थान) : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की राजनीति और हमारे प्रधान मंत्री की नीति हमेशा दूरदर्शितापूर्ण रही है, केवल दूर-

[श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत]

दर्शितापूर्ण ही नहीं बल्कि उसके साथ ही साथ एक ध्येय को लेकर रही है। जब कभी कोई नीति हमने अपनाई तो देश का हित सबसे ऊंचा समझ कर और यही हमारा ध्येय रहा है कि देश सबसे ऊंचा है। हमारा ध्येय रहा है—बहुजन हिताय, बहुजनसुखाय।

जब आज से चार साल पहले, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि बंगला देश में हमारी फौजें फतेह करती हुई आगे बढ़ रही थीं और हमारी सेनायें जब वहां पर बहुत कुछ कर सकती थीं, उस समय भी जैसे ही पाकिस्तान की सेनाओं ने अपने हथियार डाले और बंगला देश आजाद हुआ, हम ने अपने आप आगे हो कर सीज फायर का ऐलान किया। दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं उन के लिये शायद यह ताज्जुब की बात रही। कई लोग जो फासिस्ट तरीके से सोचने वाले है उन को भी यह बात, अजीब लगी, लेकिन हमारा ध्येय था उस देश को आजाद कराना, और जैसे ही वह बंगला देश आजाद हुआ, हम ने सीज फायर की घोषणा कर दी। हमारी इस प्रकार की नीति रही है। उसी नीति के आधार पर आज हम एक बिल ला रहे हैं, उसे पास कर रहे हैं और यह भी उसी नीति का परिचायक है। अगर आज हम चुनाव के मैदान में उतरें जो कि समाज में होने वाला था तो इस में कोई दो राये नहीं कि हमारी पार्टी उस चुनाव में स्वीप करती हुई इधर से उधर निकल जाएगी। आज जिस तरह का माहौल है, आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, जिस प्रकार से जनता के दिल और दिमाग में नयी निष्ठा और विश्वास पैदा हुआ है उस को देखते हुए चुनाव जीतना, बहुत जोर से जीतना हमारी पार्टी के लिये बहुत मामूली सी बात है। जो इस बारे में एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि अगर हम अभी चुनाव में उतरें तो तीन चौथाई से ज्यादा वोटों से हमारी पार्टी जीतेगी। लेकिन नहीं, हम ने एक साल के लिये चुनाव आगे टालना ही ठीक समझा है क्योंकि जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं घोषणा की है कि चुनाव में जीतना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि देश का हित साधना है। देश का हित चुनाव जीतने से कहीं बड़ा है। इस लिये देश हित को देखते हुए साल भर के लिये हम चुनाव को आगे टालने की बात सोच रहे हैं। क्योंकि हमारी जो नीति है वह मैं आप से पहले ही कह चुकी हूं। वह नीति जनता के हित के लिये है और चुनाव जो हम आगे बढ़ा रहे है एक तय शुदा चीज को देखते हुए, वह यही बताता है कि हमारी निष्ठा जनता में है और हम को अपने आप पर, अपनी पार्टी पर और अपने नेता पर पूरा विश्वास है।

इस बिल को ले कर कल लोक सभा में कई सदस्यों ने बहुत जोर से विरोध किया मुझे खुशी है कि आज हमारे शर्मा जी ने बहुत ठीक शब्दों में साफ तो नहीं मंजूर किया, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने कहा, उसे देखते हुए उन्होंने कोई खास विरोध नहीं किया। लेकिन लोक सभा में कल इस का जबरदस्त विरोध किया गया था। यह भी उन की नीति का एक अंग है। उनकी नीति रही है कि जो भी हम अच्छे कदम उठायें, जो भी अच्छे काम करें उन का विरोध किया जाये। चाहे हम एक्सप्लायटर्स के खिलाफ कानून बनायें तो हमारा विरोध होगा, या हम समाजवादी कदम उठायें तो भी हमारा विरोध होगा। अगर हम किसी इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करें तो भी विरोध किया जायेगा, अगर हम प्रिसेज के प्रीवी पर्सेज को खत्म करें तो भी विरोध किया जायेगा। यह उन लोगों की नीति का एक अंग है, हमारे किसी भी काम का विरोध करना। मेरा विश्वास है कि वह मन में खुश हो रहे होंगे कि चुनाव आगे बढ़ गया क्योंकि अभी उनकी मानसिक तैयारी

नहीं है कि वह चुनाव लड़ सकें, लेकिन वह हमारा विरोध करेंगे, दोषारोपण करेंगे इस लिये कि यह उन की नीति है, उन का धर्म है। यह वह कर रहे हैं। अगर आज हम अभी चुनाव में उतर गये होते तो यही हमारे माननीय सदस्यगण जो विरोध कर रहे हैं वह दूसरे शब्दों में बोलते। वह कहते कि यह तो मैनिपुलेशन है। हमारे साथी डी०आई०आर० में बंद हैं, हमारे नेता बाहर नहीं हैं और ऐसे समय में चुनाव कराया गया है। चाहे डी०आई०आर० में दो हजार आदमी ही बंद हों लेकिन वह बतायेंगे कि उन के दो लाख आदमी बंद हैं और इस लिये चुनाव फेयर नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है और इसी लिये हम चुनाव में जीत नहीं पाये और चुनाव में हार गये। उन के बोलने के टोन बिलकुल उस के खिलाफ होता, और यह दूसरे ढंग से उस समय बोलते। मैं उन की याद दिलाना चाहती हूं कि आज जब एक साल के लिये हमने यह चुनाव बढ़ाया है तब आप विरोध कर रहे हैं। आप को यह याद नहीं कि पिछले चुनाव में हम पांच साल पूरे होने के पहले ही, चार साल बाद ही चुनाव के मैदान में उतर गये थे। उस समय हम अल्प संख्या में थे। हमारे सामने कई तरह के सवाल थे, कई तरह की परेशानियां थीं, लेकन हम जनता का मैन्डेट लेने के लिये, जिन नीतियों की हम ने घोषणा की थी उन के लिये समर्थन पाने के लिये हम चुनाव के मैदान में उतरे थे। तब भी आप का कहना था कि एक साल पहले चुनाव क्यों कराये गये। हमारी मुसीबत है। पहले चुनाव करायें तो कहेंगे कि गलत है और बाद में कराये तो कहेंगे कि गलत है। तो आप के लिये विरोध करना मात्र ही एक बात रह जाती है।

**श्री ओउम् प्रकाश त्यागी :** ठीक समय पर क्यों नहीं कराये थे?

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत :** इस वक्त चुनाव की तैयारी नहीं है। इस वक्त आप कहगें कि क्यों पोलिटिकल बातों को उठाया जा रहा है। मुझे ताज्जुब होता है जब हमारे भाई बार-बार इस हाउस में डी० एम० के० के सदस्यगण संविधान की बड़ी-बड़ी बात करते हैं और आश्चर्य होता है यह देख कर कि उन के अपने राज्य तमिलनाडु में ही किस प्रकार से संविधान की छीछालेदर हो रही है। किस प्रकार के काम वहां किये गये हैं वह सब के सामने आयेंगे आयोग की रिपोर्ट सामने आने पर। इसी तरह से सी० पी० एम० वालों को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब वह आदर्श की बात करते हैं तो वह याद करें कि कलकत्ता में पहले क्या होता था जब वहां उन की हकुमत थी। कोई औरत सेफटी के साथ बाजार से नहीं निकल सकती थी। उस का कहीं जाना मुश्किल था और उस समय किस तरह के कांड वहां हुए जो आप सब भी जानते हैं। मैं उन को इस समय यहां दोहराना नहीं चाहती क्योंकि वक्त नहीं है। वहां का जन जीवन कभी शान्त नहीं रहा था। जिस तरह से वहां खून हुए, गुंडागर्दी हुई और आप के तमिलनाडु में आज क्या हो रहा है वह भी आपके सामने है। अभी उन का भी पता चल जाएगा कि आयोग के सामने किस प्रकार की चीजें आती हैं। अध्यक्ष महोदय, इन चुनावों को हम ने आगे क्यों टाला इस का एक कारण यह रहा है कि जो हम ने जनता से वायदा किया है, जो हम बीस सूत्री प्रोग्राम लाये हैं, जो हम आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं उस के लिये आज देश में इमरजन्सी को रहना जरूरी है। इमरजन्सी में चुनाव नहीं हो सकते, इस लिये हम ने यह किया है। देखा जाये तो हम ने एक प्रकार की रिस्क ली है, कोई पोलिटिकल फायदा नहीं उठाया है। अगर आज हम चुनाव में उतरते तो हम को फायदा होता, लेकिन

[श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत]

हम एक प्रकार से रिस्क ले रहे हैं क्योंकि जो काम करने हम जा रहे हैं, जो बीस सूत्री प्रोग्राम हम लागू करने जा रहे हैं वह आसान बात नहीं है। उस में बहुत काम है, कई तरह की दिक्कतें हैं। हम लोगों को कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन के कर्जे माफ किये जायें तो यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है। उस के लिये हम को छोटे-छोटे बैंकों की स्थापना करनी पड़ेगी करोड़ों रुपये लोगों को साहूकारों के कर्ज से मुक्त होने के लिये देना पड़ेगा और इसी तरह से दूसरे सवाल हैं सीलिंग का सवाल है। जिस जमीन को लेकर हम को बांटना है उस के लिये वक्त चाहिए। इसी लिये हम इस को ले कर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज इमरजन्सी उठा दी जाये तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे इन कामों के इंप्लीमेंटेशन में बाधायें डाली जाएंगी। जब कभी हम ने इस तरह के कदम उठाये हैं तब हमें याद है कि किस तरह के मूमेंट चलाये गये हैं, किस तरह के झगड़े खड़े किये गये हैं और हमारे उन कदमों को रोका गया है। मैं 1973 की याद दिलाना चाहती हूं कि जब हमारा देश संकट में था। अनाज बाजार में मिल नहीं रहा था तो उस समय इन पार्टियों ने लेवी लेने के लिये जब सरकार जाती थी तो किसानों को भड़काया कि सरकार को लेवी न दी जाये और शहरों में जा कर यह प्रचार करते थे कि सरकार से सस्ता अनाज मांगो। किसानों को कहा जाता था कि सरकार को लेवी न दो और उन के कहने में आ कर किसानों ने सरकार को लेवी नहीं दी और एक प्रकार से एक बड़ा संकट हमारे सामने आ गया था। यह एक नमूना था। आज इमरजेंसी के बाद हमारी बिगड़ी हालत कुछ सुधर रही है। उस में आज सुधार होता जा रहा है और इस इमरजेंसी का सभी वर्गों ने स्वागत किया है, इस का चतुर्मुखी स्वागत हुआ है। इस का स्वागत किसान ने किया है, इस का स्वागत मजदूर ने किया है, इस का स्वागत आम जनता ने किया है। आप हाउस वाइफ से पूछ लें कि जिसको क्यू में घंटों खड़ा रहना पड़ता था और उस को आवश्यक सामग्री नहीं मिल पाती थी। आज आसानी से हमें आवश्यक सामग्री मिल रही है।

हमारा उत्पादन बढ़ा है। हमारा जो प्रशासन है वह ठीक ढंग से चल रहा है। जो पहले स्थिति थी, उसमें बहुत जबरदस्त सुधार आया है और हम चाहते हैं कि हम अपने प्रशासन को और सुधारें। अभी तक हालांकि हमारी कीमतें गिरी हैं, फिर भी मैन्यूफैक्चर्ड गुड्स के दाम इतने उंचे चढ़े हुए हैं कि हम उनको गिराना चाहते हैं। आम जरूरत की चीजों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा इंपोर्ट कम करके हमारा ऐक्सपोर्ट बढ़े। हम चाहते हैं कि जो गरीब तबका है उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जा सकें। उनके लिए हम रिहायशी मकानों की, खेती के लिए जमीन की और उनके लिए रोजगार का प्रबन्ध कर सकें। इन सब हालात को देखते हुए यह जरूरी है कि इमरजेंसी कायम रहे। इसके लिए ही साल भर के लिए चुनावों को आगे बढ़ाया गया है।

आप लोगों ने हमारे देश की हालत को खराब करने के टोटल रेवूलूशन की बात कही। सारी स्थिति को बिगाड़ दिया था और आप यह नहीं सोचते, अपनी पार्टी के स्वार्थों को ध्यान में रखते ह, देश के लाभ को नहीं देखते हैं। लेकिन हमने इन सारी बातों के ऊपर, सारी हालतों के ऊपर ज्यादा गौर किया है और इस मुल्क को सुधार करके हम ठीक रास्ते पर ले जायेंगे। दरअसल में हालत यह

है कि जो हमारी पहले हालत थी, आज उसके ऊपर हमने काबू पाया है—

'वह जो कहते थे कि हम पर मौत है छाई हुई,
देख लें वो आज, हम हैं मौत पर छाये हुए।'

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra): Sir, I would crave your indulgence if, during my speech, there are a few touches of sentimentalism and a few outpourings of emotion.

MR. CHAIRMAN: The lady Member has spoken, isn't it?

SHRI N. G. GORAY: I want to say this because, yesterday and the day before yesterday, when the Bills curbing the freedom of the press have been discussed, even a man like Shri Bhupesh Gupta, not once but many times, referred to the great contribution that Shri Feroze Gandhi had made to the freedom of the press. Shri Shukla, in his reply, has said that a good deal of sentiment had crept into the debate and he deplored that. But, Sir, I am one of those who believe that sentiment and emotion are the salt of life. Not only that, Sir, but I believe that when we talk of democracy, when we talk of liberty, when we talk of equality between man and man, it is the sentiment that dictates to us, that all men should be considered equal. Otherwise, Sir, what is common between you and me, what is common between me and my friend, Shri Gokhale? And still we build the whole edifice of democracy on this postulate that all men are equal. It is a sentiment; it is an emotion; it is something intangible and still it has helped man to build noble structures, noble social structures. So, Sir, as I said, may be, sometimes in my speech occasions may arise when I would be a little sentimental. Another reason, Sir, is that we have been so much involved in this democracy.

Sir, I can remember three distinct phases in my life. One phase was that of creation, when we built up this social structure, democratic structure, parliamentary structure brick by brick, we strove for it, struggled for it during the days of pre-Independence. You were also one of the soldiers, honoured soldiers. That was the phase I would like to equate with Brahma, the Creator.

After Independence came the phase of preservation, Vishnu, when all of us, even though we belonged to the opposition parties, under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru tried to preserve the values that we had created during the struggle. And, Sir, I do hope now, I can say 'fondly hope', that a time will not come in my lifetime at least when this phase of preservation will change into the phase of destruction. That good fortune will not fall on me but today I am seeing the third phase, the third face of the Trimurti, that of destruction of whatever we had created. And one by one all the values that we had cherished are going down the drain. Where is the necessity of freedom of the press? Has not the press utilised its freedom in a wrong manner? Where is the necessity of liberty of the individual? Have they not misused it? Sir, we have come to a point where we are almost afraid of freedom. There is a well-known book written by E. Fromm, 'Fear of Freedom'.

I remember when my colleague Madhu Limaye met Mr. Brezhnev when he was visiting this country. At the end of their talk Mr. Brezhnev asked Mr. Madhu Limaye: Will you tell me what is the necessity of opposition party at all? I do not know whether that ideology has inspired us. But somehow it has come to pass that we would like to see the entire country under the control of one party. Therefore, as I said that having seen the phase of creation, having seen the phase of preservation. I am now a witness to the last phase of destruction. What will come afterwards. I do not know. Possibly, according to the Marxists dialects there was a thesis and there was an anti-thesis and may be out of that thesis and anti-thesis, out of the conflict of the two, a synthesis may emerge. I do not know what will be the phase of that synthesis, what will be the nature of that synthesis. It is very curious that while we are moving a democratic society towards an authoritarian rule, right now, in Paris the great Communist Party of France is meeting and the main thesis before that Party is, as has been reported, the Secretary-General of that Party is recommending to its Party

[Shri N. G. Goray]

that the concept of the dictatorship of the proletariat should be rejected and we must say without any reservation that we are ready to tolerate or even to encourage or even to practise democratic ideals. Sir, those of you who know what a crucial place this dictatorship of the proletariat has in the Communist's political ideology, will understand what a change has come, they are discarding it, the main idea over which the whole super-structure in Russia and other Communist countries is raised that there must be a dictatorship of one party, one class. And here one of the biggest and the strongest Communist Parties, the Communist Party in France, is saying : Let us give a go-by to this idea; it is no longer tenable. Sir, my sorrow is all the greater, that we have not understood this. It is not as if Jawaharlal Nehru had not read Marx. It is not as if, when we became free, these compulsions to which my very erudite friend referred to in his last speech were not there. India was a backward country; India was a developing country; India was a country where so many dialects and religions and other things were there in existence. And knowing all that, after a full debate lasting months and years, we had deliberately chosen this system. It is not as if we had accepted this system in a fit of absent-mindedness. With open eyes we had chosen this system—freedom of the press, all the civil liberties, everything. And, Sir, now we find that we are rejecting them one by one. I would only like to point out to my friend Mr. Gokhale that it is my misfortune that, having worked with him for years, today I find myself in a position which is very, very unfortunate. But these are the facts of life. One has to face them.

Sir, I would like to ask you : Are there not other democratic countries in the world which had to undergo all these strains and stresses? Have we not heard of the mammoth dragon march in Japan in the period after the Second World War? In France Sir, so many times has the Communist Party of France not tried to paralyse the entire thing—industry, government, social life? But does it mean that because all these things happened. Japan has not prospered? Sir, Japan has registered the highest rate of annual increase in national, income—more than what the capitalists western world think they could achieve, more than what they themselves thought they could achieve. Has France not become one of the most affluent nations of the world, in spite of all these strains and stresses? But in this country, Sir, because somebody said something, because there was some agitation, because somebody talked of total revolution, because Rajnarain used to create trouble here, all sorts of excuses had been trotted out, and now it is being said that everything is so calm. There also there are these contradictions. Sir, what is it? Has the emergency succeeded; or has the emergency not succeeded? On the one hand, you say it has succeeded. Sir, I will point out to you that on September 13, 1975 our Home Minister Shri Brahmananda Reddi, was put this question in Madras. Is the situation normal? And Brahmananda Reddi said : Normalcy prevails all over the country. That was on September 13. But, most probably, Brahmananda Reddi does not represent the mind of the Government; I can see that. But surely the Prime Minister does represent the mind of the Government, the heart of the Government. What did she say when she gave an interview to the North German television on October 3, 1975? She said : There is peace everywhere. September—normalcy is everywhere; peace is everywhere and after that, November, December, January, February—four months have passed. And still, our Law Minister, our Home Minister, our Prime Minister, all these people sitting on those Benches are coming to this House and are saying that there is no normalcy still, that they want to extend the life of the Lok Sabha because there is no normalcy. And to the press, to the foreign people, they say, there is normalcy, there is peace everywhere. And I do not see how you can contradict that statement that there is peace. Of course, there is peace.

Sir, I am one of those who have held that there was no justification for emergency at all. There were strikes—yes; there were quarrels, there were conflicts. But suppose for argument's sake that there was conflict, that there were strikes, that there were anti-national activities. Now, you have yourself said that there is normalcy not only in one part of the country but throughout. That is what you said. This is what the Home Minister says in Madras.

And after four months, the Tamil Nadu Government itself is toppled—why?—because there is normalcy in Tamil Nadu.

AN HON. MEMBER : Too much normalcy.

SHRI N. G. GORAY : Therefore, what are all these things due to? The taproot is, in panic they thought that there was emergency everywhere. That is the taproot of all this mischief and because that taproot is there, you saw the necessity for emergency, the MISA, the Defence of India Rules, the curtailment of civil liberties. And to what extent? Your representative in the Supreme Court has the audacity to say to the Judges that once the emergency is declared, even if a man is shot, he has no remedy. Perhaps, he was logical because once the emergency is declared, he can see no reason for the other laws of civil liberty, etc. to exist. But is that the state of affairs that you want to cherish in this land?

Sir, when I referred to the debates that had taken place in the Constituent Assembly years back, I found that Dr. Ambedkar, Shri Kamath and so many other eminent personalities like Pandit Bhargava, all of them, had devoted days and days to discussing this emergency. And Dr. Ambedkar went to the extent of pointing out that this is not a simple matter; it is not as if you are to treat emergency in a normal way. And therefore, in the Constitution when the emergency powers are given, the wording used is not only 'emergency' but 'grave emergency'. After all, words have some meaning. They could have only stated 'whenever the Government feels that there is an emergency'. No. They said, 'grave emergency'. Was there a grave emergency in this country before? Is there a grave emergency in this country today? Then, why is it that you are basing your argument that because there is emergency, the life of Parliament is to be extended by one year?

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa) : Mr. Goray...

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala) : Orissa Government is speaking.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Do not try to influence me. I am asking him a question.

MR. CHAIRMAN : Let him finish his speech.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : After what happened in Gujarat and in Bihar, don't you think that the situation was grave?

DR. K. MATHEW KURIAN : This is a graveyard of democracy.

SHRI N. G. GORAY : Sir, I have always respected my friend. *(Interruption)* Please, I never interrupt you. Please bear with me. I am not going to speak here many times now. Perhaps it is the last speech.

DR. V. P. DUTT (Nominated) : I hope, of this session.

SHRI N. G. GORAY : Well, next session I may come. So what I am saying is, look at the debates in the Constituent Assembly. Dr. Ambedkar said that when this emergency is declared and when the powers under the emergency are exercised, it is "evasion of Parliamentary law"; he used those words; he said it was evasion. Look at the gravity with which they were considering the whole aspect. And when Mr. Kamath and others opposed it, he said "Don't suppose that I do not share your views. I do. But I hope that this will not happen and it will be a dead letter." And even where you want to take over or dismiss any Government, look at the words that he has used—I am referring to the Constituent Assembly debates, page 177, where he said :

> "If at all they are brought into operation, I hope the President, who is endowed with these powers, will take proper precautions before actually suspending the administration of a province. I hope the first thing he will do would be to issue a mere warning to the province that has erred that things were not happening in the way in which they were intended to happen in the Constitution. If that warning fails, the second thing for him to do will be to order an election allowing the people of the province to settle matters by themselves."

This was the scheme of things. First you give them a warning. If they do not behave, if the Cabinet does not behave, if that province does not behave, then he says the next natural thing to do is to ask

[Shri N. G. Goray]

for elections. What are you doing? You are not only not allowing them to hold elections but you are postponing your elections also by one year. Sir, is it not a travesty of the Constitution, of the article that was meant to be used only in exceptional cases, in "grave emergency" not merely emergency? And he says that emergency must end as soon as possible. Just now I have quoted the Home Minister as well as the Prime Minister saying four months back that there was normalcy everywhere. Still you are saying that emergency is there. Where is the emergency? It is in your mind. You want to see ghosts everywhere. And that is because you want to perpetuate your rule. It is not for consolidation of the gains of the emergency but because you want to consolidate your own power.

Sir, I would like to ask what was wrong in Tmail Nadu. They had 165 members in a House of 235. They are ready to go to the polls. They only asked that the polling to the Parliament as well as to the Legislative Assembly should be synchronised. It is a very natural demand because those who cannot afford to spend crores of rupees would like to see that both the elections are held together. You did not allow it. That is all right. After three weeks, they would have gone. But you could not wait. You brought in all sorts of allegations. Sir, I will deal with those allegations when you give us an opportunity to discuss it. But supposing again that your allegations were true, what is the position in the neighbouring State of Karnataka? Is it not a fact that the Congress Committee itself has submitted a memorandum to the High Command of the Congress saying that this Government of Mr. Urs should go? Sir, here is a paragraph from a document....

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka) : Sir, where is he quoting from ?

SHRI N.G. GORAY : Please sit down. I do not think you are well posted with information.

Sir, the document I am quoting from is a note on the state of affairs of the Congress Party in Karnataka submitted to the honourable Prime Minister with eight annexures and, in the paragraph which is called the "Conclusion", they say—it is on page 12 of the memorandum—

"The High Command is aware...."—Think of it—"The High Command is aware of the state of affairs in the State. There are several means of ascertaining these drawbacks. Suffice it to say...."—This is from the Congress Party itself—"suffice it to say that the continuance of the Devraj Urs Ministry any longer would spell disaster to the Congress organisation in the State and it would be very difficult for the Congress to face the election in the future."

DR. K. MATHEW KURIAN : Then they can postpone the elections to the future.

SHRIMATI MARGARET ALVA : Mr. Goray, where are you quoting from? ..(*Interruptions*)... Where are you quoting from ?

SHRI N.G. GORAY : I know how eloquent you are.... (*Interruptions*)....

I know how eloquent you are. Please do not interrupt...

MR. CHAIRMAN : No interruptions, please. You go on, Mr. Goray.

SHRI N.G. GORAY : So, what I am saying is this that this is from the horse's mouth itself. This is from the horse's mouth. It is not an afterthought like that of Shri K.K. Shah, the Governor of Tamil Nadu, who has been sitting there in Tamil Nadu for the last five years and who has been awarding certificates of merit to this Ministry and he has been saying in his Address to the Legislature that this Ministry is functioning properly. I will quote from it when the time comes. And now, all of a sudden, you have discovered so many things! What was he doing all these years? All these allegations are three years old or four years old. And, Sir, what was he doing? Because the Centre wanted the dismissal at this particular point of time that the Governor obliged them. And, when the Karnataka Congress Committee itself is saying that it will be a disaster to that State if they allow the Devraj Urs Ministry to continue, you just cannot hear those words! So, Sir, I would like to ask you this. Is this fair? Is this justice? Is this even-handed justice under the Constitution? Is it the proper use of the emergency? To every one of these questions, Sir, the answer is "No". (*Time bell rings*).

MR. CHAIRMAN : You have taken more time.

SHRI N.G. GORAY : Please allow me some more time.

DR. K. MATHEW KURIAN : You have extended the term of the Lok Sabha and you can extend the speech also; you can extend the time of the honourable Member also.

MR. CHAIRMAN : I think you will have to finish now. You will get an opportunity later.

SHRI N.G GORAY : Sir, I rarely go beyond the time-limit, you know ...

MR. CHAIRMAN : Please finish.

SHRI N.G. GORAY : I will just finish in ten minutes.

SHRI BANARSI DAS (Uttar Pradesh) : Sir, you can give him our time. We will give him our time also.

SHRI N.G. GORAY : Sir, the most surprising thing is that it is not as if the Congress people do not know what they are doing. Had it been so, it would have been all right. But it is not so. Sir, I am reminded of that famous sentence in the Mahabharata. It is the utterance of Duryodhana. He said :

जानानि धर्मम् न च मे प्रवृत्ति:
जानान्यधर्मम् न च मे निवृत्ति:
केनापि देवेन हृदिस्थितेन
यथा प्रवृत्तोस्मि तथा करोमि ।

Arjuna never knew what was there in Duryodhana's mind. He said :

"I know what is wrong; but I cannot desist. I know what is right; but I cannot do it. Some demon has taken possession of my soul and it looks as if everything is revolving as if we are helpless."

Sir, I am clear that in a democracy the people are not helpless nor is the Government helpless. Let us not do it.

Sir, In this House, I have again and again pleaded that this country cannot afford to have such a civil strike. It cannot be divided into two groups, those who are good and those who are bad. Let us come together; and let us evolve a national consensus. But, Sir, in spite of my knocking, 12 Noon no door is open. In spite of the knocking by Jayaprakash Narayan, the door still remains closed. And, Sir, I am sorry to say that in spite of Acharya Vinoba Bhave's knocking, the door still remains closed...

(*Interruptions*).

SEVERAL HON. MEMBERS : No, no.

SHRI N.G. GORAY : Sir, Acharya Vinoba Bhave invited the Acharyas throughout the country, and..

DR. V.P. DUTT (Nominated) : Acharya Vinoba Bhave is hand-picked by Shriman Narayan....(*Interruptions*).

SHRI N.G. GORAY : You are such a learned man. You must have read this small pamphlet. I am reading this quotation from a booklet containing speeches delivered by Acharya Vinoba Bhave at the 'Akhil Bharat Acharya Sammelan' held on 16th, 17th and 18th January, 1976, at Wardha :

**सर्वसम्मत निवेदन**

'विगत घटनाओं के लिये किसी पर दोषारोपण न करते हुए सम्मेलन मानता है कि अब देश के अन्दर की स्थिति को सामान्य रूप देने की प्रक्रिया का आरम्भ करना एवं एकता और परस्पर सहयोग के वातावरण का निर्माण करना अति आवश्यक है, ताकि प्रधान मंत्री के शब्दों में 'प्रजातंत्र की गाड़ी पुन: पटरी पर लाई जा सके'। वर्तमान गतिरोध का उचित, सम्मानयुक्त एवं शीघ्र हल प्राप्त करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जाने चाहियें। प्रजातांत्रिक मूल्यों, तरीकों एवं संस्थाओं से ही हमारे देशवासियों के सही हितों का संरक्षण हो सकता है और वे ही सम्भाव्य बाह्य खतरों का मुकाबला करने के लिये बड़े पक्के साधन है समय अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुचित विलम्ब से स्थिति बिगड़ सकती है और अनिष्ट परिणाम आ सकते हैं। वर्तमान स्थिति के चालू रहने से युवा-पीढ़ी पर होने वाले परिणामों के विषय में सम्मेलन ने विरोध रूप से चिन्ता व्यक्त की'।

I cannot improve upon it.

SHRI RANBIR SINGH (Haryana) : But.....*(Interruptions)*.

SHRI N.G. GORAY : Mr. Ranbir Singh why do you interrupt? I never want to be hard with you. I know, you would like to crush everybody, but still...

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala) : You have the Haryana Police with you.. *(Interruptions)*.

SHRI N.G. GORAY : I am saying that there are good people on this side and there are bad people on your side also. Let all the good people in the nation come together. And if you do not like it, you can go your way. You are going your way.

I will only end by saying this. I remember the great oration of Antony when Julius Ceasar was murdered. He said, Sir, when Julius Ceasar fell :

"And, in his mantle muffling up his face,
Even at the base of Pompoy's statua (Which all the while ran blood), great Ceasar fell.
O, what a fall was there, my countrymen!
Then I, and you, and all of us fell down...."

So, therefore, Sir, I would like to say : Don't bury democracy. Don't stab it like this. If democracy fells, then I would only say :

What a fall was there, my countrymen!

By democracy, I mean : I, and you, and all of us fell down. This is my last appeal.

**श्री कल्पनाथ** (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो पालियामेंट के एक्सटेंशन का यह बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके सामने अभी बहुत सी बातें नाना साहब के द्वारा रखी गयीं। क्योंकि एक साल पालियामेंट का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है? 26 जून के पहले और 26 जून के बाद की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 26 जून के पहले हिन्दुस्तान के अन्दर विरोधी दल के लोगों ने और दुनिया के साम्राज्यवादी मुल्कों ने जो स्थिति बना रखी थी उसके कारण 26 जून को आपत्कालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 26 जून के पहले देश में ही नहीं दुनिया के पैमाने पर जहां एक ओर अमरीकी साम्राज्यवादी और माओ बादी चीन दोनों उभर कर हिन्दुस्तान की आजादी के खिलाफ एक षड़यंत्र कर रहे थे, दूसरी ओर 26 जून के पहले हिन्दुस्तान की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, भारतीय लोकदल जैसे नाना प्रकार के सिद्धांतों को रखने वाली पार्टियां ... हिन्दुस्तान के अन्दर लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास कर रहीं थीं। क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं कि फोर्ड साहब ने अमरीका की सेनेट में भाषण करते हुए कहा कि साइनो-अमरीकन रिलेशनशिप इज परमानेंट फीचर।

गोरे साहब ने कहा कि गांधी जी ने हिन्दुस्तान को आजादी दिलाई। जवाहर लाल नेहरू ने हिन्दुस्तान को लोकतंत्र दिया। मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान की आजादी की और हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की रक्षा के लिए 26 जून को आपत्कालीन स्थिति की घोषणा की गई। क्या डियेगो-गार्शिया में अमरीकी हवाई अड्डे का निर्माण हिन्दुस्तान की आजादी के लिए खतरा नहीं है? क्या हिन्द महासागर के अन्दर साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा अपने बेड़ों को ले जाने की घटना हिन्दुस्तान की आजादी के लिए खतरा नहीं है? क्या चीन का तिब्बत में परमाणु अड्डे का निर्माण करना हिन्दुस्तान की आजादी के लिए महान खतरा नहीं है? क्या साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा पाकिस्तान को अरबों-खरबों के अस्त्रों से लैस करना हिन्दुस्तान की आजादी के लिए एक महान खतरा नहीं है? हिन्दुस्तान के अन्दर प्रजातंत्र की बात करने वाले नाना साहब गोरे से मुझे निवेदन करना है कि प्रधान मंत्री की सभाओं में गोह, बिच्छु और सांप फेंकना

क्या प्रजातंत्र है? चुनी हुई विधानसभाओं को भंग कराना क्या प्रजातंत्र है? क्या जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभाओं के चुनावों में विधायकों का हरण करना प्रजातंत्र बतलाया था? क्या विधायकों के घरों को जलाना प्रजातंत्र है?

नाना साहब गोरे गीता की बातें करते हैं। लेकिन जब हम गोरे साहब को देखते हैं तो हम उनको उस स्थिति में पाते हैं जो कौरवों के बीच में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की थी। ऐसी ही स्थिति गोरे साहब की आज विरोधी दलों के बीच में है। एक तरफ जनसंघ पार्टी है जो लोकतंत्र की दुश्मन है, जो फासिस्टवाद की समर्थक है, जो प्रजातंत्र को जड़मूल से नष्ट करना चाहती है, एक तरफ चीन की समर्थक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है और इन दोनों दलों का समर्थन नाना साहब गोरे जैसे आदमी कर रहे हैं। उनकी वही हालत है जैसी घड़े शराब में एक बोतल दूध की होती है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी को खतरा दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतों से 26 जून के पहले था। हिन्दुस्तान की आजादी को खतरा हिन्दुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मार-काट, कत्ल का जो वातावरण देश के अन्दर बनाया गया था, इन दोनों स्थितियों के कारण, साम्राज्यवादी और माओवादी अंतर्राष्ट्रीय षड़यंत्र और हिन्दुस्तान के प्रतिक्रियावादी पार्टियों के षड़यंत्र दोनों के कारण जो हिन्दुस्तान की आजादी खतरे में पड़ गई थी, हिन्दुस्तान का लोकतंत्र जो लुप्त होने जा रहा था, इन दोनों स्थितियों का मुकाबला करने के लिए प्रधान मंत्री ने 26 जून को देश में आपत्कालीन स्थिति की घोषणा की। क्या 26 जून के बाद हिन्दुस्तान की राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार नहीं हुआ है, इसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जीवन की आवश्यक वस्तुओं के दामों में 25 प्रतिशत की कमी हुई है। देश की खाद्यान्न की चीजों में 10 परसेंट दाम गिरे हैं। रेल यातायात में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। रेलों और देश के पैमाने पर ठीक समय पर चलना देश की जनता के लिए महान स्वागत का कदम है। चाहे जीवन की आवश्यक वस्तुओं के सामान हों, चाहे यातायात के साधनों का ठीक ढंग से देश के अन्दर चलना हो, इन सारी बातों ने हमारे देश के अन्दर एक बहुत ही अनुशासन की स्थिति को पैदा किया है। कालेजों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में जो जगह-जगह हुल्लड़बाजी का वातावरण पैदा किया गया था, देश के अन्दर जो एक पढ़ाई लिखाई के वातावरण को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, वह वातावरण देश के पैमाने पर समाप्त हुआ है। सारे देश के अन्दर एक अनुशासन का वातावरण पैदा हुआ है। सवाल यह उठता है कि इस अनुशासन के वातावरण को देश में कायम रखा जाए। मिलों और कारखानों की हड़तालें बन्द हुई हैं। रेलों के अन्दर जो देश के पैमाने पर भ्रष्टाचार था, उसके अन्दर कमी हुई है। मार-काट, खून और कत्ल का जो ऐटमासफियर पूरे मुल्क में बनाया जा रहा था वह पूर्णरूपेण शान्त हुआ है। पार्लियामैन्ट के अन्दर हम कहते हैं कि नार्मल स्थिति नहीं है लेकिन आप गांवों में चले जाइये, शहरों में चले जाइये पूरे देश की जनता ने इस आपातकालीन स्थिति का स्वागत किया है। इससे देश का जन-जीवन सामान्य हुआ है। स्कूल, कालेजों की पढ़ाई ठीक ढंग से चलने लगी है। कारखानों में उत्पादन बढ़ा है। जीवन की आवश्यक चीजें लोगों को अवेलेबल हो रही हैं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत की प्रधान मंत्री ने और इस देश की सरकार ने आपातकालीन स्थिति

[श्री कल्पनाथ]

को कायम किया है और इसी वातावरण को कायम रखने के लिये पार्लियामैन्ट की टर्म एक साल के लिये बढ़ाई जा रही है। यह टर्म इसलिये भी बढ़ाई जा रही है कि जो हमारे राष्ट्रीय जीवन में अनुशासन की भावना आई है यह अनुशासन की भावना आदत के रूप में परिणत हो जाए। यह नेशनल हैबिट बन जाए। लोग जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासनबद्ध हों और राष्ट्र के निर्माण कार्य को करें इसलिये भी इस टर्म को बढ़ाया जा रहा है।

आज प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि चुनाव जीतना या न जीतना हमारे लिये उतनी बड़ी चीज नहीं है जितना राष्ट्रीय जीवन में अनुशासन को कायम रखना, आर्थिक उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्र की नींव को मजबूत करना, राष्ट्रीय आर्थिक जीवन में संतुलन को कायम रखना है। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक बैलेंस मेन्टेन करने के लिये तथा आर्थिक उत्पादन की वृद्धि के लिये पार्लियामैन्ट की टर्म को जो एक साल के लिये बढ़ाया जा रहा है इसका हम स्वागत करते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के लोग यह तर्क देना चाहेंगे कि हम चुनाव डर के मारे नहीं करा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में जब कि विरोधी दल की सरकार कायम है तब भी गुजरात में पंचायत के इलेक्शनों ने साबित कर दिया है कि हिन्दुस्तान की जनता किस के साथ है। आज सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, आज सवाल यह भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आज सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम और आप सब मिल कर इस देश के लिये क्या करें जिससे देश की आजादी कायम रह सके, देश का लोकतंत्र कायम रह सके।

अभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात की गई है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और विष्णु ने उसका पालन किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा देश आजाद हुआ। उन्होंने एक आजाद मुल्क की रचना की और इस आजादी को कायम रखने के लिये तथा इसकी प्लांड इकोनोमी को बढ़ाने के लिय जवाहर लाल जी ने समाजवाद के आधार पर इस मुल्क के निर्माण का सपना देखा।

जापान की बात की जाती है। कहा जाता है कि अमेरिका में प्रजातंत्र है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका और जापान की परिस्थितियां हमारे देश की परिस्थितियों से भिन्न हैं। दुनिया का एक खेमा साम्यवाद के तरीके से विकास करना चाहता है और दुनिया का दूसरा खेमा पूंजीवाद के तरीके से विकास करना चाहता है लेकिन हम पूंजीवाद और साम्यवाद से हट कर एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं। जो लोकतंत्र के आधार पर होगी। जवाहर लाल नेहरू जी ने प्लांड इकोनोमी और डेमोक्रेसी की हिन्दुस्तान में आधारशिला रखी थी और इसी प्लांड इकोनोमी और लोकतंत्र के लिये हिन्दुस्तान में प्रतिक्रियावादी ताकतों ने, दक्षिणपंथी ताकतों ने एक भयंकर खतरा पैदा किया। आप जानते हैं कि इसी कारण हमारी प्रधान मंत्री जी को देश में आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। नाना साहब गोरे जब प्रजातंत्र की बात करते हैं मेरी समझ में नहीं आता तब वह क्यों मिलिटरी का आह्वान करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब ब्रिटेन की पार्लियामैन्ट का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे देश में आया था तो उन्होंने कहा था कि हम जय प्रकाश जी के प्रति आदर की भावना रखते हैं लेकिन मिलिटरी को पालिटिक्स में दखल देने के लिये जो आह्वान किया गया है उसके खिलाफ प्रधान मंत्री का एक्शन महान है।

मैं इस बात को नहीं समझ सका कि जब आचार्य विनोबा भावे ने आपात्कालीन

स्थिति को एक अनुशासन पर्व की संज्ञा दी है तो श्री नाना जी गोरे गीता के श्लोकों की बात क्यों कह रहे हैं। मैं उन्हें गीता के इस श्लोक की याद दिलाना चाहता हूं :—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥

जब कौरवों का दल एक तरफ था और सर्वनाश करने के लिए उतारू हो गया था तो भगवान ने आगे आकर उसका सामना किया। इसी प्रकार से जब मार्क्स-वादी कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योति बसु और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी एक होकर हिन्दुस्तान की आजादी को खतरे में डालने के लिए कलकत्ता की सड़कों पर इकट्ठे हो कर नेतृत्व कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की ताकतों को रोकना आवश्यक हो गया था।

आदरणीय उप-सभापति महोदय, मुझे एक बात और कहनी है। हमारे देश में आपात्कालीन स्थिति की घोषणा की गई और अब इस विधेयक के द्वारा एक साल के लिए लोक सभा की अवधि बढ़ाई जा रही है। मैं समझता हूं कि इस पार्लियामैन्ट की जो अवधि बढ़ाई गई है, वह 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए ही बढ़ाई गई है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर इस बढ़ी हुई अवधि में आपने 20 सूत्री कार्यक्रम पर अमल नहीं किया तो हिन्दुस्तान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने कांग्रेस पार्टी के विघटन के समय देश की जनता के समक्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही और फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आपने प्रिवीपर्स समाप्त किया। इसके साथ-साथ आपने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का वचन देश की जनता को दिया था। इस प्रकार का आश्वासन बम्बई के अधिवेशन में दिया गया था। आज आपने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के माध्यम से नई सामाजिक आर्थिक रचना का देश की जनता को वचन दिया है। इसलिए यदि आप 20 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में समय-बद्ध रूप से योजना बनाकर एक साल के अन्दर कार्य नहीं करेंगे तो देश की जनता आपको क्षमा नहीं करेगी।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और कारखानों में बनने वाली चीजों और खेत में पैदा होने वाली चीजों के दामों में संतुलन कायम किया जाय। आज हिन्दुस्तान के अन्दर समस्त गरीबों को ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि केवलमात्र 50 ग्रामीण बैंक खोलकर हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीबों की ऋण की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। इस 20 सूत्री कार्यक्रम ने हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों के मन में एक ऐसा दीप जलाया है, एक विश्वास का अंकुर प्रस्फुटित किया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। आज हमारे देश के करोड़ों गरीब लोग इस बात को अहसास करने लग गये हैं कि वे एक आजाद देश के नागरिक हैं। वे चाहते हैं कि हमारे देश में समाजवादी समाज की रचना के लिए एक ठोस, समयबद्ध कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस देश की गरीब जनता को साहूकारों, सेठों और पूंजीपतियों के हाथ से निकालकर प्रगति के पथ पर लाने के लिए जो आश्वासन दिये गये हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए और समाजवादी आधार पर नई लोकशाही के निर्माण के लिए सरकार को अधिक से अधिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना करनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी देहात के करोड़ों किसानों के मन में नई आशा का दिया जला

[श्री कल्पनाथ]

सकेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार ने बम्बई अधिवेशन में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का जो आश्वासन दिया था उसको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। सन् 1971 में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का जो वचन दिया गया था उसको पूरा किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI G. LAKSHMANAN : Mr. Deputy Chairman, Sir, I oppose this Bill for the reason that it is a political prostitution committed by the Government of India in asking for an extension of one more year when we have been asked to remain as Members of Parliament only for five years....

SHRI KAMESHWAR SINGH (Bihar) : You people are corrupt and that is why you see everybody in that light.

SHRI G. LAKSHMANAN : Shall I continue, Sir? This is an act of political prostitution by the Government of India and, therefore, I oppose this Bill. Sir, in the year 1971, we, the parliamentarians, contested the elections and the people of this great country of ours allowed us to be Members of Parliament for five years. And now, when we are completing five years, we have gone astray because, we are married to democracy, our husband is democracy, and we, as ladies or wives of democracy, are now going astray without going to the people again asking for that marriage. Therefore, I say, this is an act of political prostitution committed by the Government of India.

Sir, this Government is famous for so many firsts in this country. This is the Government which introduced, first of all, internal emergency in the country. This is the Government which has postponed elections for the first time in this country. Since the year 1947 when we got independence there is not a single occasion when the Government of this country under the leadership of the great democrat of the world, Shri Jawaharlal Nehru, or under the leadership of Shri Lal Bahadur Shastri asked for the extension of its life but today our respected Prime Minister is asking for extension. This Government is famous for so many things which it is doing for the first time. The previous Governments never arrested the Deputy Prime Minister, never arrested their own party-men without any reason and never arrested politicians and parliamentarians under the M.I.S.A. Of course, they might have taken some of the people under the D.I.R. Therefore, this Government is famous for so many number ones. And, today another act that they are committing is this political prostitution.

Sir, after the completion of five years you ask for extension and though we have had 27 years of independence and democratic existence in this country, we have no machinery which could decide whether an extension could be granted to the Central Government or a State Government. These decisions are taken politically by the Central Government. The Government of Tamil Nadu would have completed its tenure in another 35 days. The Government of Kerala have already completed their tenure but they have been granted an extension because the Congress Party and the Communist Party have formed an alliance there. Now, today the Central Government wants an extension of one year for them. They will have it because they have already passed the Bill in the Lok Sabha and they will have it passed here also. But, what is the machinery to decide whether a Government is to be granted an extension or not, including the Central Government? It is therefore that I say that this is a political decision. Since the D.M.K. party is an opposition party and that Party is an example or a challenge to the Congress Party, they do not want that Party to continue.

What has actually happened in Tamil Nadu? A memorandum was given, containing charges, corruption charges, nepotism, favouritism and all that. You must remember what this Government did from 1972 till January 1976. In January 1976 the Governor of Tamil Nadu comes to Delhi, stays in the Tamil Nadu House for ten days, interview is not granted to him for the first two or three days, he goes back to Gujarat or Bombay, then comes back to Tamil Nadu House, stays there and everything is finalised here. On the 26th of January, on the Republic Day, the Governor of Tamil Nadu has said that the most efficient Government which has implemented the best policies in India is the Government of Tamil Nadu. And

everything was prepared here and then he goes back to Madras. Sir, I would say, we do not mind; the Chief Minister of Tamil Nadu has already welcomed the appointment of the Commission and he has said to the people not to get alarmed however much we are being terrorised and harassed and that we must conduct ourselves peacefully; that is our culture. Therefore, we are conducting ourselves peacefully. We are not worried that a Commission has been appointed, but the means that this Government adopts, a Government that is run on so-called Gandhian lines, a Government that is run on democraitc lines, what are the means that this Government adopts to remove another Government? Is it because they were elected by the people and they have the verdict of the people to continue for five years and rule this country? Just now, honourable Shri Goray said as to what the President should do with regard to the action being taken against a State Government. He read out what Ambedkar had said. Therefore, I would say this extension should not be given to this Government for all this maladministration, introduction or promulgation of Emergency, arrests of so many people including the ex-Deputy Prime Minister of India and arrest of Jayaprakash Narayan releasing him to go to the hospital only. All these acts of commission and omission are in the political interest of the Congress Party and for the continuance of a particular personality as the Prime Minister of India. Therefore, Sir, an election is a dire necessity as far as this Government is concerned. Any democratic Government, any political party in the world goes and asks for the verdict of the people. But what happens here? Fifty-eight crores of people are not fools. If you are bold you should say that your action is good. What have you done in introducing Emergency? If you are really men of courage get the verdict of the people. Therefore, Sir, this is an act of cowardice because such an act is committed only by a coward. You must go to the people and ask for their verdict. You have brought so many laws like abolition of bonus; so many laws you have brought in. Should you not go to the people and get their verdict as to whether what you have done in the name of Emergency is liked by them or not? Should you also not tell them that you have brought in a very good scheme, called the 20-point programme which is going to have, instead of water in the Ganges, honey and milk? You can go and tell the people. Why are you afraid? If your 20-point programme is a programme for the people, is a programme for the nation to flow instead of water in the Ganges, honey and milk, why can't you go to them? Why are you afraid? That is why I say that this Bill is an attempt at political prostitution. This Bill is...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Lakshmanan, you seem to be very fond of the word "prostitution"- You have said it four times.

SHRI G. LAKSHMANAN : I do not want to use the word "prostitution" Sir. I add the word "political" also. I do not like that. According to our culture, you know, Sir, we are famous for our Kannagi and all that? Therefore, you are comitting the word "political".

SHRI MANUBHAI SHAH (Gujarat) : You can use a better word.

SHRI G. LAKSHMANAN : If there is any better word, tell me.

SHRI MANUBHAI SHAH : I will tell you when I speak.

SHRI G. LAKSHMANAN : Sir, I would tell you that this word is not used by me personally against anybody or against any party. In Tamil it is called "*Arasial Vibacharam*".

Now, for this 20-point programme, why can't you go to the people? You say certain Governments have not implemented it, the Tamil Nadu Government has not implemented it. What have the advisers said? They have said that this 20-point programme can be implemented provided the Centre comes forward to help the States and provided the co-operation of the Centre is there. That is what our Chief Minister was also telling. Not only that, as far as the administration and other aspects are concerned, is the Government prepared, when they have appointed a one-man Commission, to appoint a Commission—let it be one-man or two-man Commission—to go through the past 27 years of rule, both at the Centre and the States by the Congress Party and the Opposition Party? Then, they can get the verdict of the people. Will they do it? If they do it, so many things will come out. They will not do it.

[Shri Lakshmanan]

If they appoint a commission to go into the acts of omission and commission of the Congress Party, the truth about the Nagarwala case and so many other things will come out. Sir, a memorandum was submitted by even our CPI friends against Mr. Bansi Lal who is now the Defence Minister of India.

SHRI YOGENDRA SHARMA : Our party had submitted a memorandum against the Karunanidhi Ministry.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He is very well aware of that.

SHRI G. LAKSHMANAN : You can criticise anybody. We are not worried about it. What happened to that memorandum? A memorandum of the type given by Mr. Kalyanasundaram was submitted to the Government against Mr. Bansi Lal. What action was taken ? He becomes the Defence Minister and he goes and says in Haryana that he, as one of the citizens of the 58 crores of the people of this country, owes his personal loyalty to the Prime Minister of this country. The memorandum disappears somewhere. There is another thing.

SHRI SULTAN SINGH (Haryana) : The charges were baseless.

SHRI YOGENDRA SHARMA : Despite my clarification, the hon. Member is repeating that our party had submitted a memorandum against Mr. Bansi Lal. Our party had not submitted a memorandum against Mr. Bansi Lal, but against the Karunanidhi Ministry. I would like to put the record straight.

SHRI G. LAKSHMANAN : Have you not submitted a memorandum against Mr. Bansi Lal?

SHRI YOGENDRA SHARMA: I would repeat again that our party had submitted a memorandum only against the Karunanidhi Ministry. This is the real fact.

SHRI SULTAN SINGH : Mr. Lakshmanan, don't compare Mr. Bansi Lal with Mr. Karunanidhi. The hon. Governor had given his report.

SHRI G. LAKSHMANAN : Of course, as you and I are different, Mr. Karunanidhi is Mr. Karunanidhi and Mr. Bansi Lal is Mr. Bansi Lal. I know that a commission will not be appointed. I would ask the Congress friends on the other side to tell me as to what more fit case can there be than the Nagarwala case to appoint an enquiry commission. In this country, a person can take lakhs of rupees from the State Bank through a telephonic conversation. No action was taken on this. But you can appoint a commission even on vague charges against a Chief Minister of a State ruled by opposition, but you are not prepared to appoint a commission against Mr. Devraj Urs, as has been said by Mr. Goray.

SHRI SULTAN SINGH : You should not forgot that an enquiry commission was appointed to go into the charges against the late Shri Pratap Singh Kairon who was a Congress Chief Minister.

SHRI G. LAKSHMANAN : I know that. I also know that there are many Pratap Singh Kairons in the Congress Party now. Of course, this Government, under the constitutional protection, can extend the life of the Lok Sabha by one year. They say that they want this extension for implementing the twenty-point programme of the Prime Minister. But the Prime Minister had stated that it would take a generation to implement this twenty-point programme. This has come in the papers. Now, the Government is taking this decision to postpone the elections. Who are involved in this? No MP will oppose the extension of the life of the Lok Sabha by one year. The affected people themselves who may become beneficiaries are taking this decision to postpone the elections by one year. Who will oppose it? Nobody will oppose it. For one more year, they will not have to go and face the people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You will have to wind up now.

SHRI G. LAKSHMANAN : Sir, I am winding up. Therefore, Sir, as I said, only a judicial commission can decide whether an extension can be granted to a State Government or the Central Government. This is a constitutional lacuna and I would suggest that a provision should be made in this regard in the form of a constitutional amendment. Simply because a State is ruled by another opposition party, you do not grant extension or you do not allow elections to take place. Whereas, in regard to another State, extension will be granted, I do not know for how long. They are going to do it. Therefore, as far as I am

concerned, my Chief Minister is not worried about this Commission. There is a proverb in Tamil : *Idukkan varumgal naguda.* We do not want to offend anybody. We are a political party who can take this decision from the Central government and also face them squarely.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, how are you going to wind up?

SHRI G. LAKSHMANAN : Only one minute, Sir.

Sir, dog is the most grateful animal, but man is not as grateful as dog. In the year 1971, why did the DMK support Mr. Giri? Only to see that the Prime Minister's candidate was elected as the President so that there would be normalcy and not chaos and confusion in the country. Therefore, Sir, dog is the most grateful animal. Man is not as grateful as dog. Thank you.

SHRI MANUBHAI SHAH : Mr. Deputy Chairman, Sir, I am glad to support this Bill even though it affects the life of only Lok Sabha. My friend, Mr. Lakshmanan of the DMK had been mixing up two issues because of the present situation in Tamil Nadu. He did not realise that the decision to extend the life of the present Lok Sabha by one year was not taken after the DMK Government was removed but much earlier. It was in the interests of the country because the situation in the post-emergency period has created many favourable results and set in the process of restabilisation of this great country. It was necessary because a brief period of extension would do what was desired to be done when emergency was imposed. In this august House, Mr. Lakshmanan and other friends had already concurred in the matter of emergency and therefore, I am surprised that a subjective view is being taken here by Mr. Lakshmanan's party. They are opposing today because they are mixing up the issue of the Tamil Nadu Government with the present Bill. Therefore, I would like to request this hon. House to take a dispassionate view of this Bill.

What is the objective of this Bill? Parliament has taken upon itself to extend its life by one year, during emergency, as is absolutely provided in the Constitution by the founding fathers of the Constitution. Now what is the difference between grave emergency and emergency as Nanasaheb Goray tried to point out? A great amount of profit has been generated because of this emergency compared to the chaos prior to that and I am really surprised that my friends there still do not appreciate it. What was the condition of the students and the youth in the pre-emergency period, during the last two or three years? No university functioned. I was on the Court of the Banaras Hindu University. It was an absolutely pitiable sight. Whenever we went to the Court of the Banaras Hindu University, the boys were on the rampage. It was not because the students did not want to study, not because they did not want to learn. They entered the portal of the university with the sacred vow that they would further their education, but they were misguided by some people, leaders of some Opposition parties and others. I do not want to name them; they have been named umpteen times. But I do not want to name the people. As Mr. Goray said there are good people there also : we admit it. But what amount of violence was taking place there! There were 29 Vice-Chancellors. How were some of the Vice-Chancellors manhandled by some of the very unruly elements, inspired and incited by some political groups! What violence, chaos and ragging! But what is the condition now? What is the condition today?

Only the other day we went to Banaras. Sixteen thousand students are studying in Banaras. I have been associated with the Banaras Hindu University for many years but for the first time in my life I saw 16,000 boys joining the procession and hearing one of the most illustrative speeches from the Vice-Chancellor. Could we say the same thing of the Delhi University two years back? When elections were common, the Jana Sangh and others were there as if some great battle was going on inside the Delhi University campus. The confusion was total. Was it becoming of the great country of Mahatma Gandhi, Krishna or the Buddha? I do not think anybody even in the Opposition was ever satisfied with the conditions that were prevailing then. Now, is this period of six months or eight months enough to stabilise the forces, to put into process not only the economic but the social and political philosophy to which our

[Shri Manubhai Shah]

Constitution is wedded, to which our Indian National Congress had subscribed? Therefore, I would again ask Mr. Lakshmanan not to use the words 'political abuse' and all that. He was repeating these words but merely by using such words in anger you do not get a point.

SHRI G. LAKSHMANAN : You give me the words. I wanted to use these words also. You tell me the words and I will use them.

SHRI MANUBHAI SHAH : We have made correct use of the political power, in the interest of the people, but you went on doing all that and I will come to that when I come to the matter of Tamil Nadu, why the Government had to be removed. Therefore, I would first appeal to the House and ask: What is there if the term of the Lok Sabha is extended by one year? The other day, the Prime Minister in an interview said that the elections would be held within a period of one year. So, heavens are not going to fall if the term is extended by one year. Democracy is not going to be smothered or we are not going to butcher the people because there is extension of the Lok Sabha. After all, this House continues for six years and the Lok Sabha continues for five years. One year is not a period about which so much excitement should be there.

Extension of one year is all the more necessary to implement the programmes of *garibi hatao* and 20-point programme which have been initiated for the removal of poverty. It is for the first time that the removal of poverty has been made the first and foremost task and fundamental approach of the Congress Party to which practically the entire nation has subscribed. This 20-point programme is only a commentary on the concrete *garibi hatao* programme. It is a concrete, identified and time-bound programme during which targets have to be achieved in different fields, particularly for the vulnerable and poorer sections of the community.

When we thought of the bonded labour, a question was asked as to why we did not think of them earlier. In this connection, it may be said that any political thinking and its development takes place according to the signs of the time. As the people get more and more awakened, naturally the cry and the voice of the poorest of the people become heard because they are the majority of voters in this country and they decide the fate of the Parliament, who will come to Lok Sabha and who will come to Rajya Sabha. Therefore, to get awakened is not the fault of a sleeping man. We may have done many things. We laid the foundation of democracy in this country. So, we are not at all complacent or ashamed that we did not do it earlier. Now, a programme of concrete character has been chalked out. Even the Janata Morcha Government of Gujarat or the DMK have subscribed to this. As a matter of fact they defend themselves when we say that we are not satisfied with the implementation of the 20-point programme either in Gujarat or Tamil Nadu. They try to defend themselves. That means, they have accepted validity of this programme.

One-year extension of the Lok Sabha is all the more justified because you cannot have elections when emergency continues. Emergency has got to be allowed to continue. If we were afraid of elections, we would not have a gone to polls in 1971. As that time, the Lok Sabha had completed only four years. Then also there was opposition. Some of them went to the extent of saying that we did not have majority in this House and that is why we were going to polls. And my friend of the DMK who is using all these words against us today, he fully supported us. They fully supported us.

SHRI G. LAKSHMANAN : You wanted our support.

SHRI MANUBHAI SHAH : Even today we want everybody's support. Even today we want your support.

SHRI G. LAKSHMANAN You wanted our support but we never wanted your support.

SHRI MANUBHAI SHAH : We never bargain. We want the support of the entire nation. (*Interruptions.*) Mr. Lakshmanan, I have heard you patiently but the point is, the very protest shows the guilty to conscience. Now I will come a little bit to the DMK because he has been saying a great deal.

If you see the certificates given by the Governor of the State, if you see the reports coming from Tamil Nadu during the last

few years, it is not only corruption but something else, something debasing the human nature and human character which is involved. It will all come out, my dear friend. You wait . . . (*Interruption by Shri G. Lakshmanan*). Now better you do not cross talk like that. Wait and have patience . . .

(*Interruption*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Lakshmanan, Let him have his say.

SHRI MANUBHAI SHAH : Sir, who appointed the Chagla Commission? When I was the Minister of Industries, Mr. Krishnamachari was the Finance Minister. He welcomed the appointment of the Chagla Commission against him. Who appointed a Commission against Biju Patnaik? Who appointed a Commission against Mr. Pratap Singh Kairon? This party has the record of doing all this throughout the last 25 years . . . . (*Interruption*). Please listen. You can talk to me in the lobby later on. Sir, I am appealing to him through you to have patience.

Don't become too much touchy. This politics is a hard bargain and in the political life you need not be oversensitive. Sir, I am appealing to him to believe that we have not spared even the highest men in the country. Against Mr. K. D. Malaviya there was not a single charge, only his Secretary was involved in an amount of Rs. 10,000, but immediately a Supreme Court judge was asked to go into the matter. And for no fault of his, he left the government. Therefore, the Congress Party has always held its character high. We have not appointed a Commission because you had an Opposition Government. We appoint a Commission wherever we find that the charges have some validity, there is some element of truth . . . . (*Interruption*). It should have been done earlier. As a matter of fact, the other day, we had a talk . . .

(*Interruption*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Lakshmanan, you kindly hold on for a while. You cannot disturb the proceedings of the House. It is all right if you make one or two interruptions, but you cannot go on interrupting like this.

SHRI MANUBHAI SHAH : Sir, he has to be patient. The point is that here we are not afraid of any political maligning. We have been maligned in elections, character assassinations have been made. I am glad the Prevention of Publication of Objectionable Matter Bill has been passed in the House the day before yesterday; it will bring some code of conduct and ethics in the country. Otherwise, wild charges unsupported by facts were being brought in, and memorandum after memorandum became the order of the day. We have stabilised the country and if we do not act now the future generation of the country will blame the two Houses of Parliament for having neglected their duty.

Therefore, the DMK Government deserved the removal. What were the politicians of the DMK Government doing in Malaya, Singapore and Hong Kong? They were collecting money in the name of Annadurai and various other people. Today they are talking of Mahatma Gandhi. They have no right to take the name of Mahatma Gandhi. While he was alive, they did not take his name. But today it suits Karunanidhi to take his name. Well, if you have turned to Gandhi, it is again our gain. But then behave like the followers of Gandhi. Therefore, Sir, I am merely saying that the removal of the DMK Government has nothing to do with the present Bill.

Sir, last time Mr. Goray said: Today the bell tolls for me, tomorrow, Mr. Ahmad, it will toll for you. I have already spoken enough. So I need not speak on these things. But the bell is tolling for the country, neither for Mr. Goray, nor for Mr. Ahmad, nor for the Congress Party. If you do not take care of the situation and see that the norms of public behaviour are properly understood—opposition can be there; there can be difference in programmes; there can be difference in goals; but the means to the end must be absolute public honesty and public conduct—we cannot take any action.

Public ethics and public behaviour should not be undermined by the types of things that were happening in Madras or elsewhere. These cannot be tolerated by this country which has a great tradition of morality and spiritual wisdom.

Sir, as I was saying, now is the time to coolly think of the Bill without passions. Mr. Goray quoted Vinobaji. Well, Vinobaji's speech has been circulated. We have read all the versions, both by the pro-

[Shri Manubhai Shah]

Vinoba's faction and others who are opposed to him. There is nothing in that which he has not supported. 'Anushasan parva' was not invented by the Congress Party; those are the words of Vinobaji. This is what everybody has said, what the Prime Minister has said, that while discipline is continuing, various other types of things which improve matters should be brought about. That is the purpose of this Bill. During the emergency we want to consolidate the gains that are achieved. When the train which has been temporarily derailed by the forces of the opposition is put back on the rails,we will come back to the normal conduct and normal way of dealing with things. That is why all these different types of enactments are being brought into existence to correct this type of distortion that has appeared in the political, social and economic life of this country. Therefore, the entire effort of the Government at the Centre and at the States where the Congress is ruling is to bring back the norms of public behaviour and public conduct so that excesses are not committed. I would not name Mr. Karunanidhi's party; they will themselves realise what they have done and why they have suffered. If they are really pure, there is nothing to fear from the Commission and they can really cooperate with them.

I would end up by saying that the values of democracy to which Mr. Goray is often referring have to be really looked at in their proper perspective. He is a great and learned friend of mine. Every time he stresses them. We have been born in freedom, we have all fought for freedom. We removed the British Empire, the largest empire in the world, by unity of strength and purpose. Likewise, all the Opposition groups today should cooperate with the Government not only in regard to this Bill but also in regard to all the programmes that have to be implemented on the political, social and economic fronts so that we can create a new country by removing all these distortions which had been created during the last three or four years by the rampage of anti-democratic elements—I would not call them as some people said as fascist elements, but would call them a conglomeration of evil forces. An Anand Margi Avadhoot yesterday said, "I did not commit five murders but eighteen murders." I was shocked that a man can murder another man under the evil spell of the so-called Ananda Murthi and kill people in cold blood and then he says, "I did not feel anything because it was the order of the Sarkar." Please do not harbour these types of people. Let there be political opposition but let there not be forces like the RSS. Mr. Tyagi is sitting there—one of the finest men. I have worked with him in several Committees. But what are the forces that are backed up by them? What are the forces that the Jana Sangh and the RSS are creating in the country? There is time to rethink over that. There can be political opposition to the right; there can be a centrist opposition; there can be a leftist opposition because, after all, it is the assence of democracy that there should be either two parties or multi-parties to swing the pendulum according to the will of the people. But one has to analyse the content. Is the Bharat Varsha the monopoly of the RSS? Or is it that a great India has to be created by the polity consisting of Hindus, Muslims, Christians, Parsis, Sikhs and other millions of people who live in this country? If ours is to be a country of all religions and creeds, then we have to rethink over the values of some of the Opposition parties who have developed a tendency to have para-military forces backing them in order to achieve their political ends. Don't be a tool in their hands. That is the only appeal that I would like to make to my friends on the Opposition. We are all on common ground. There is hardly any difference created between the people on the opposite side and people on our side. But the means have to be such, the types of instrument to be forged is to be such that we should really be able to create a great country with proper understanding rather than have a civil war or a cold war which will divide this country or which will disturb the peace of this country.

With these words, I would once again appeal to the members of the Opposition Group not to take this Bill amiss. We can go to elections any day. We have proved it from time to time. If we go to elections even today, I would say that we would get a thundering majority because we are seeing public opinion also. The Gujarat Panchayat election about which I do not want to mention repeatedly has clearly proved that the bulk of the people are with us even

in an area which is ruled by an opposition Government. Mr. Lakshmanan said that you dismissed our Ministry. In Gujarat, the Prime Minister clearly assured that we are not interested in the dissolution of the Assembly nor are we interested in dismissing the Ministry. If they can be in power there today, we can also be there in power tomorrow. Therefore, we want opposition but the opposition has to be of a rational type. And we are not afraid of elections. Even if it is held today, we will win in the elections. The elections are postponed up to one year as suggested in this Bill.

Sir, with these words, I support this Bill.

**श्री सीताराम सिंह** (बिहार) : श्रीमन्, उपसभापति महोदय, इस बिल पर बोलने से पहले मैं ये पंक्तियां कहना चाहता हूं:

> "टांक रहे हो सुई चर्म पर,
> शांत रहें हम तनिक न बोलें
> यही शांति ? गर्दन काटती हो
> फिर भी अपनी जीभ न खोलें?"

श्रीमन्, यह बिल काला भी है और हमारे संविधान के निर्माताओं की जो इच्छा थी उसके प्रतिकूल है, जनतांत्रिक ढांचे के प्रतिकूल है। यह बिल राष्ट्रघाती है। श्रीमन्, गांधी जी के नश्वर शरीर की नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी, लेकिन इस बिल के जरिए बापू जी के तथा कथित चेले जो आज सत्ताधारी दल में विद्यमान हैं, वे लोग उनकी आत्मा की और उनके उसूलों की हत्या कर रहे हैं। श्रीमन्, आज अपने देश की क्या स्थिति है? सारे जनतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया गया है, सारी मान्यताओं को खत्म कर दिया गया है, और सारी परम्परा को खत्म करके एक तानाशाही का वातावरण अपने देश में कायम किया गया है। यह बहुत दुखद स्थिति है और इस स्थिति पर गंभीरता से इस सदन को विचार करना चाहिए; क्योंकि डण्डे का राज बहुत दिनों तक दुनिया में नहीं चलता है। श्रीमन्, दुनिया का इतिहास साक्षी है, जब जनता उठ खड़ी होती है तो दुनिया में बड़े-बड़े तख्त और ताज को गिरा देती है। डण्डा राज अगर कायम रहता तो मुसोलिनी और हिटलर आज तक राज करते, कभी वे नहीं हटते। लेकिन हर जगह जनतांत्रिक मूल्यों के बल पर कोई भी शक्ति राज करती है—जन इच्छा और जन भावना के बल पर—न कि संगीन के बल पर। संगीन के बल पर अगर राज्य चलता रहता तो अंग्रेज हमारे देश से नहीं जाते, जिन अंग्रेजों के राज्य में सूरज नहीं डूबता था। लेकिन जब जनता ने विद्रोह किया तो वे भी चले गए। तो मैं सत्ताधारी दल के दोस्तों से कहना चाहता हूं और बात आदर से कहना चाहता हूं कि गंभीरता से स्थिति को सोचें और समय से पहले चेतें वरना देश की स्थिति विस्फोटक होगी और उस का दायित्व उन पर ही होगा जो कि अभी सत्ता में हैं और सत्ता चला रहे हैं।

श्रीमन्, आज दुहाई दी जा रही है आपात-कालीन स्थिति की। मैं मानता हूं, संविधान में भी आपात-कालीन स्थिति का प्रावधान है। लेकिन किस समय? उसके भी कुछ मुद्दे हैं। आज अपने देश में कोई अर्थ-व्यवस्था फेल नहीं कर रही है आज अपने देश में कोई सशस्त्र आंतरिक विद्रोह नहीं हो रहा है, आज कोई विदेशी हमलावर हमारे मुल्क पर तोप और फौज और टैंक लेकर हमला नहीं कर रहा—इन तीनों में कोई भी स्थिति अपने मुल्क में नहीं है फिर भी आपात-स्थिति लागू है और कुछ दिनों से नहीं, यह भी 8 महीने से लागू है और इसकी संभावना नहीं है कि कब तक यही स्थिति बनी रहेगी। दुहाई दी जाती है इस आपात-कालीन स्थिति की कि उसके जरिए अनुशासन हुआ है, गाड़ी, टाइम पर चलती है, दफ्तर के बाबू लोग समय पर दफ्तर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गाड़ी समय पर चलाने के लिए, दफ्तर के बाबुओं को समय पर आफिस में जाने के लिए आपात-कालीन स्थिति क्या दुनिया के इतिहास में कहीं और भी

[श्री सीताराम सिंह]

लागू की गई है? यह तो सामान्य प्रशासन का काम है। तो इससे ही साबित होता है कि आप प्रशासन चलाने में कितने क्षम्य, कितने योग्य रहे हैं। जो प्रशासनिक काम हैं उनको भी आपने ठीक से नहीं किया, अपने कर्त्तव्य से च्युत रहे और सारी जनता को आपात-कालीन संकट में झोंक दिया। यह स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह से कुछ तरक्की हुई है। क्या तरक्की हुई है? लोग कहते हैं कि मूल्य कम हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपने लायक दोस्तों से जो उस बेंच पर बैठे हुए हैं कि कल कारखानों की पैदावार और खेती की पैदावार के मूल्यों में कोई संतुलन है। आज भी आपतकालीन स्थिति में कीमत गिरी है तो कच्चे माल की कीमत गिरी है। पक्का माल जो बड़े-बड़े उद्योगपति इस देश में बनाते हैं उसकी कीमत नहीं गिरी है। आज भी शोषण किसका हो रहा है? जो मजदूर है, जो किसान है, जो कच्चा माल पैदा करता है उसका शोषण हो रहा है। आग जलाने की लकड़ी 12 रुपये 13 रुपये मन बिकती है, लेकिन गन्ने की कीमत भी 12--15 रुपये क्विंटल है। शोषण किसका किया जा रहा है? जो कमजोर लोग हैं, जो असंगठित हैं, जो किसान हैं उनका शोषण किया जा रहा है। ढोल पीटा जा रहा है समाजवाद का। बीकर सेक्शन्स को उठाने का, अछूतों को उठाने का, उनको जमीन देने का। श्रीमन् आज क्या हो रहा है। अभी-अभी अखबार में आया था कि बांदा जिला जहां श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ था वहां दो हरिजनों को कत्ल कर दिया गया; क्योंकि उनको जमीन का पर्चा मिल गया था। आज यह अपने देश की स्थिति है और यह बहुत भयानक स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई एक पक्षीय बात करके राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है, अगर लोकतंत्र की तरक्की करनी है तो तमाम विरोधी दल के लोग जो जेलों के अंदर बंद हैं उनको आप बाहर कीजिये, फिर एक साथ बैठिए और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के निर्माण के हेतु प्रोग्राम चलाइये और देखिए कि कौन आपके साथ सहयोग करता है और कौन नहीं करता।

1 P.M.

श्रीमन्; आज बहुत दुखद स्थिति है। आचार्य विनोबा भावे ने एक आचार्यों का सम्मेलन किया और उस सम्मेलन के प्रस्ताव लेकर माननीय श्रीमन्नारायण जी दिल्ली आये। एक सप्ताह तक यहां रहे, लेकिन उनको श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू जो हमारे देश की प्रधान मंत्री हैं उनसे मिलने का मौका नहीं दिया गया, जिससे कि वे प्रस्ताव दे सकते और उन पर बात कर सकते। इसी से अंदाजा किया जा सकता है कि कितनी दूर तक आप सहयोग चाहते हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं कुछ मित्रों का पत्र भी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के पास गया, लेकिन उन्होंने उत्तर भी देना जरूरी नहीं समझा। जहां तक 20-सूत्री कार्यक्रम का सवाल है, देश में क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज भी वही लूट, वही शोषण, वही अत्याचार, वही पक्षपात का बोल बाला है।

बीस सूत्री कार्यक्रम कोई वेद नहीं है, कोई उपनिषद नहीं है, गीता नहीं है, कुरान नहीं है। श्रीमन्, आप को तो बहुत ज्यादा इस बात की जानकारी है कि गरीबों की गरीबी हटाने के लिये, भूमिहीनों को जमीन देने के लिये, जो बेरोजगार हैं उन को रोजगार देने के लिये, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये, मंहगाई खत्म करने के लिये विरोधी दल के लोग, हमारे जैसे लोग प्रत्येक साल लाठी और डंडा खाते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं और जेल के सींखचों में बंद हो कर तरह-तरह की यातनायें सहते रहे हैं। यह कोई नयी चीज

नहीं है। अगर इसको आप करना चाहते हैं तो ठीक है। अच्छी बात है। आप कीजिए। आप को कोई रोकता नहीं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि एक लकीर ब्रह्मा की खींच दें कि इसके आगे कोई नहीं जा सकता और न कोई इस से पीछे जा सकता है। आप दरवाजा खुला रखिये। अगर आप देश को बनाना चाहते हैं तो उसके लिये आप की बड़ी जिम्मेदारी है, आप की बड़ी पार्टी है, आप के हाथ में सत्ता है। आप उस में विरोधी पक्ष के लोगों को भी लीजिए और बैठ कर विचार कीजिए कि यह बीस सूत्री कार्यक्रम है। इस पर आप के भी कोई सुझाव हों तो दें। बीस सूत्री कार्यक्रम में क्या है? शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम में कहीं इस बात का उल्लेख है कि चाहे वह राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान हो, दोनों को एक ही स्कूल में एक ही तरह की तालीम दी जायेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आमदनी और खर्च की सीमा बांधने का कोई उल्लेख आप के बीस सूत्री कार्यक्रम में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप रास्ते को खुला रखिये और तमाम विरोधी दल के लोगों को आमंत्रित कीजिए और फिर विचार कीजिए और तब प्रोग्राम चलाइये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जनता की अपार शक्ति होती है। उस के सामने सभी को घुटने टेकना पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूं बहुत अदब के साथ अपने लायक दोस्तों से कि समय रहते चेतो। डंडे का राज बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। अगर समय रहते नहीं चेत गये तो एक बहुत बड़ा बवंडर होगा और पता नहीं उस में सरकार कहां जायेगी और हम कहां जायेंगे, यह कहना मुश्किल है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

Mr. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2.00 P.M.to day

The House then adjourned for lunch at seven minutes past one of the clock.

---

2.00 P. M.

The House reassembled after lunch at one minute past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman in the Chair.**

## THE HOUSE OF THE PEOPLE (EXTENSION OF DURATION) BILL, 1976—*contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Dr. Kurian.

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to oppose this Bill. Sir, this Bill, if it is passed, will further reduce the Constitution and the democratic process into a sheer mockery. Sir, this Bill is a motivated one and a *mala fide* one, and is a flagrant misuse of power just because the Congress Party have a majority and they want to perpetuate their rule. Sir, extending the term of the Lok Sabha is a very extraordinary proposition. It is extraordinary because the emergency, which is used as a pretext for extending the Lok Sabha, itself is a fake emergency. Sir, this is another glaring example of misuse of constitutional provisions. It is true that the Constitution does provide for Parliament to enact Law for extending its own life. But, nonetheless, it is an outrage on the spirit of the Constitution. The constitutional provision is to be used only in exceptional cases. Sir, emergency is attempted to be turned into a normal affair in this country. There is a conscious attempt at propaganda, political campaign, and the use of the Press and other media to legitimize the emergency and to give the impression that abnormal emergency situation itself is normal. This is an attempt at political legitimation which the ruling party is attempting. During the next one year, the ruling party naturally wanted to use the time available to them to make an unfavourable situation, according to them, a possibly favourable situation.

Sir, all this claim that if they had gone to the polls they would have won with a thumping majority, is a false claim, because, according to our best knowledge, people in this country, though they are not speaking out because of the emergency provisions and because of the draconian laws, are fuming in themselves, and definitely the situation will recoil against the Government itself.